गन्ने की पेमेंट नहीं मिलने से सड़कों पर उतरे किसान

[जयश्री भोसले | पुणे]

महाराष्ट्र में गन्ना की पेराई शुरू हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। गन्ना किसानों ने भुगतान के खातिर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों के प्रदर्शन के कारण राज्य में होने वाली पेराई पर असर पड़ा है, लेकिन चीनी मिलों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (उचित और लाभकारी मूल्य या एफआरपी) तय किया है, उसका भुगतान वह एक किस्त में नहीं कर सकती हैं। इस बीच, एक हफ्ते से कम में चीनी की कीमतों में 11 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है।

इस बीच, 11 दिसंबर को नागपुर में राज्य के शीर्ष नेताओं- शुगर दिग्गजों, प्राइवेट इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के बीच हुई मीटिंग में गन्ना के भुगतान पर गतिरोध खत्म करने के लिए 80:20 के फॉर्मूले पर सहमति बनी। किसानों के प्रतिनिधि एफआरपी का 80 फीसदी अभी और 20 फीसदी बाद में लेने के लिए तैयार हो गए। हालांकि, सोलापुर में कुछ चीनी मिलों ने एफआरपी के 80 फीसदी से कम का भुगतान किया है, जिसके कारण स्वाभिमानी सेतकारी संगठन ने सोमवार से कई इलाकों में गन्ने की कटाई पूरी तरह से बंद कर दी है।

स्वाभिमानी सेतकारी संगठन के फाउंडर लीडर राजू शेट्टी का कहना है, 'हमने विरोध-प्रदर्शन इसलिए शुरू किया है, क्योंकि चीनी मिलें एफआरपी का 80 फीसदी भुगतान करने से जुड़े अपने वायदे पर कायम नहीं रही हैं।' शेट्टी ने कहा कि चीनी की कीमतें बढ़कर 29 रुपये किलो के स्तर पर पहुंच गई हैं और कोल्हापुर रीजन में हाई रिकवरी है, ऐसे में शुगर मिलें एफआरपी का भुगतान कर सकती हैं।

कोल्हापुर में डालमिया शुगर को उस समय ऑपरेशंस शुरू करने की इजाजत दी गई, जब मैनेजमेंट ने एफआरपी का 80 फीसदी भुगतान करने को लेकर अंडरटेकिंग दिया। शेट्टी का कहना है, 'जब चीनी मिलें एफआरपी का 80 फीसदी भुगतान कर देंगी तो हम विरोध-प्रदर्शन बंद कर देंगे।'

30 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 1,281.16 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को बकाया था, जिसमें से चीनी मिलों ने 25.31 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और अब 1,255.85 करोड़ रुपये के एरियर का भुगतान किया जाना है।